# रोजगार का भविष्य

वर्तमान कौशल और दक्षता भविष्य के रोजगार के अवसरों के अनुकूल नहीं हैं और जो नयी क्षमता हासिल की जा रही है, वह भी जल्दी ही अनुपयुक्त हो जायेगी. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विशेष रिपोर्ट में इस चुनौती का रेखांकन किया है. भारत समेत पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के तेजी से बदलते स्वरूप के कारण बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, मशीन और तकनीक के तेजी से बढ़ते दायरे ने सेवाओं, सुविधाओं तथा सामानों के उत्पादन और वितरण में सहूलियत तो पैदा की है, लेकिन इनकी वजह से मानव श्रम की मांग भी कम होती जा रही है. बीते दिनों दावोस में विश्व आर्थिक फोरम के सम्मेलन में भाग ले रहे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के शीर्ष नेतृत्व ने भी उत्कृष्ट तकनीक से लैस मशीनीकरण से बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जतायी है. श्रम संगठन की रिपोर्ट में 187 सदस्य देशों से सामाजिक न्याय, विषमता घटाने और कामकाज की बेहतरी पर आधारित 'मनुष्य-केंद्रित एजेंडा' बनाने का आह्वान किया है. अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, या फिर बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के साथ सरकारों और उद्योग जगत का रवैया वैसा ही रहेगा, जैसा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर है? तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और आर्थिक बढ़ोतरी की जरूरत मौजूदा सभ्यता के सच हैं. लेकिन, रिपोर्ट का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि रोजगार के मसले को तकनीक और तकनीकी विशेषज्ञों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है. विकास का लक्ष्य लोगों के जीवन को समृद्ध बनाना है. इस प्रयास में समान अवसरों को सुनिश्चित किये बिना न्याय और शांति की स्थापना संभव नहीं है. भारत से लेकर फ्रांस तक में रोजगार और आमदनी के सवाल पर आंदोलन हो रहे हैं. अमेरिका जैसे कुछ देशों द्वारा अपनायी जा रही संरक्षणवादी नीतियों के पीछे भी रोजगार एक बड़ा तर्क है. इसी के परिणामस्वरूप व्यापार युद्ध जैसे प्रकरण हमारे सामने हैं. विश्व व्यापार संगठन के नियमों और जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपायों पर विकसित और विकासशील देशों में तकरार का कारण भी यही है कि हर देश अपनी आर्थिक समस्याओं के हिसाब से नीतियों को स्वीकार या अस्वीकार कर रहा है. रोजगार न होने से वंचना से ग्रस्त लोगों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी आमदनी मुहैया कराने का मुद्दा अक्सर चर्चा में रहता है. जैसा कि श्रम संगठन के प्रमुख गाइ राइडर ने कहा है, काम करना मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और बिना काम के माहौल में आमदनी की गारंटी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए. भारत के साथ अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं तथा छोटे और मंझोले उद्योगों में विकास की बहुत संभावनाएं हैं. सरकार, समाज और उद्योग जगत को इन आयामों को प्राथमिकता देकर रोजगार के भविष्य का आधार बनाना चाहिए.

**समान अवसरों को सुनिश्चित किये बिना न्याय और शांति की स्थापना संभव नहीं है. भारत से लेकर फ्रांस तक में रोजगार और आमदनी के सवाल पर आंदोलन हो रहे हैं.**

# पर्यावरण की चिंता जरूरी

**जगदीश रत्तनानी**
वरिष्ठ पत्रकार
editor@thebillionpress.org

**जिन लोगों ने पर्यावरण संकट खड़ा किया है और मौजूदा व्यवस्था बनाये रखने में जिनकी बड़ी भागीदारी है, वे इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते. इनमें उनकी बड़ी संख्या शामिल है, जो हर साल दावोस के जश्न में देखे जाते हैं.**

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) लगभग आधी सदी पुरानी संस्था है. यह खुद को सार्वजनिक-निजी सहयोग करनेवाले अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में पेश करती है और वैश्विक आर्थिकी सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. अपने सफर की शुरुआत में इस मंच ने विश्व की एक हजार प्रमुख कंपनियों के लिए सदस्यता की एक व्यवस्था बनायी थी. स्वाभाविक है कि इसने अपने सालों के सफर में भविष्य पर विचार करने के लिए महंगी और खूबसूरत जगहों पर बैठकें आयोजित कर बड़ी व्यावसायिक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों में एक साख बना ली है. आमतौर पर इसके बैठकों का एजेंडा व्यापक होता है, लेकिन स्वर और मुख्य अभिप्राय कारोबार ही- व्यवसाय के लिए व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय द्वारा- होता है. और अब व्यवसाय जगत इन मुद्दों- परेशान युवा, सरकारों पर अविश्वसनीयता, दुनियाभर में बढ़ती असमानता और आर्थिक लूटपाट- को लेकर चिंतित है. ऐसे समय में सहयोग का ग्राफ कैसे आगे बढ़ेगा?

हाल में संपन्न सम्मेलन दावोस- 2019 में दो बयान आये हैं, जो कुछ चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं. इनमें से एक बयान 92 वर्षीय प्रकृतिवादी सर डेविड एटेनबरो का है, जिन्होंने विश्व की मौजूदा स्थिति पर एक पंक्ति का नाटकीय और मर्मस्पर्शी निष्कर्ष दिया कि 'इडेन गार्डेन अब नहीं रहा'. दूसरा बयान दिग्गज वैश्विक सलाहकार एसेंचर की ओर से आया है, जिन्होंने अहम बात रखी- 'भरोसा ही वास्तविक मुद्रा है'. हालांकि कई वक्ताओं ने इसके तीव्र क्षरण की ओर ध्यान दिलाया था.

इस तरह दावोस ने बाहरी और भीतरी बदलावों के लिए उठी आवाजों में तालमेल बिठाया. इसके अतिरिक्त, यह मंच जिस रास्ते पर आधी सदी तक सफर कर चुका है, उस पर आगे बढ़ने को लेकर चुनौतियों से निपटने की चिंता अभी कायम है. जिस पथ पर इसने अभी तक की यात्रा की है, उसकी प्रकृति अतीत और भविष्य को लेकर बहुत बदली नहीं है. अंतः यह एक आर्थिक मंच है और इसकी चिंता वैश्विक मानी जा रही दुनिया में विकासमान कारोबार के बीच गरीबी दूर करने के उपाय के तौर पर आर्थिक विकास को आगे ले जाना है. जबकि यथार्थ में वैश्विक दुनिया का अस्तित्व नहीं है.

विश्व आर्थिक मंच की प्रमुख चिंता का विषय था- 'वैश्विक अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से गुजर रही है', इसलिए इसके दृष्टिकोण और चिंताओं को समझें. समृद्धि, सहयोग और सुरक्षा ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलानेवाले तीन कारक हैं. यह समझना आसान है कि वरीयता और समृद्धि किसके लिए है? आर्थिक विकास ने असमानता को कम नहीं किया, बल्कि बढ़ाया है. ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलनों के पहले असमानता में वृद्धि दर्ज की जाती है. बदहाली बढ़ी है और स्थितियां और बदतर हो रही हैं.

पिछले साल दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ी है, यानी एक दिन में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर. पिछले साल, 26 लोगों के पास उतनी संपत्ति थी, जितनी 3.8 बिलियन गरीबों की कुल संपत्ति थी. वैश्विक वित्तीय संकट शुरू होने के बाद से अरबपतियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गयी है. साल 2017-2018 के बीच लगभग हर दो दिन में एक नया अरबपति पैदा हो हुआ. इसी अवधि में, धनवान लोग और कॉरपोरेशन पिछले दशकों की तुलना में निम्न दर की करों का भुगतान कर रहे हैं!

ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के आंकड़े स्तब्ध करनेवाले हैं. भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 2004 के 49 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2017 में 479 बिलियन डॉलर हो गयी थी. और यह सिर्फ 100 धनवानों के पास थी. भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति देश की जीडीपी का 15 प्रतिशत है. दिलचस्प है कि लगभग 40 प्रतिशत भारतीय अरबपतियों को उनकी संपत्ति विरासत में हासिल हुई है, जबकि यह संपत्ति अरबपतियों की कुल संपत्ति का दो-तिहाई ही ठहरती है. साल 2005 और 2010 के बीच रीयल इस्टेट क्षेत्र के सभी 15 अरबपतियों ने इस अरबपति क्लब में जगह बनायी. वहीं दूसरी ओर, आईटी क्षेत्र के अरबपतियों की संपत्ति की विकास दर कम रही है.

इन सबके बीच जो तस्वीर उभरती है, वह दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं- गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अधिकतर लोगों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के अवसरों की बात नहीं करती है. वैश्वीकरण हमारे लिए घनिष्ठता और सीमाहीन दुनिया लेकर नहीं आया. सीमाएं उनके लिए खुली हैं, जिनके पास साधन हैं, लेकिन वे साधनहीनों की पहुंच से बाहर हैं. पूंजीवादी व्यवस्था और अधिक शोषणयुक्त कारोबारी रवैयों ने उपभोक्तावाद पैदा किया, जिसने पर्यावरण प्रणाली को हाशिये पर डाल दिया है.

कॉरपोरेशनों में बैठे, ऊंची योग्यता वाले पेशेवर तथा प्रबंधक और उनके अगुआ क्या कर सकते हैं, जब दुनिया की हालत अपने आप में इतनी खराब हो? आखिर वे कार और सड़क की कितनी मरम्मत कर सकते हैं, जब गंतव्य ही भाग्य भरोसे हो और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों की बदहाली के भरोसे पर छोड़ दिया गया हो, जो एक प्रजाति के रूप में हमारा संरक्षण करते हैं.

ये ऐसे बड़े सवाल हैं, जिनका सामना करने में विश्व आर्थिक मंच असमर्थ है. जिन लोगों ने यह संकट खड़ा किया है और मौजूदा व्यवस्था बनाये रखने में जिनकी बड़ी भागीदारी है, वे इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते. इनमें उनकी बड़ी संख्या शामिल है, जो हर साल दावोस के जश्न में देखे जाते हैं. ये लोग नींद में चलनेवाले बटालियन के अगुवा हैं, जो दावा करते हैं कि दुनिया एक मशीन है, जिसे थोड़ा तेल डालने और कुछ पार्ट बदलकर ठीक से चलाया सकता है. जबकि, पूरा ढांचा ही बेकार हो चुका है, किसी बदलाव के लिए यह जानना जरूरी है.

जलवायु परिवर्तन के सवाल पर सर एटेनबरो ने सही कहा कि 'इसे बढ़ा-चढ़ाकर कहना कठिन है, हम आज इतने अधिक हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने तरह के तंत्र हैं, जो पर्यावरण प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलेगा. हमें पहचानना होगा कि हम जो सांस लेते हैं और जिस भोजन को खाते हैं, वह सब कुछ हमारी प्रकृति से ही मिलता है.'

(अनुवाद: कुमार विजय)

# बजट में हो 'भारत' पर नजर

**निशिकांत दुबे**
सांसद, लोकसभा
delhi@prabhatkhabar.in

**आगामी बजट को 'भारत' के लिए होना चाहिए, जिसमें ग्रामीण जरूरतों पर खास ध्यान दिया जाये. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें आवश्यक कदमों की एक पूरी शृंखला का ही सहारा लेना होगा.**

वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट एक ऐसे वक्त में पेश होने जा रहा है, जब पूरा विश्व जटिल आर्थिक परिस्थितियों का शिकार है. विश्व की बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में अपस्फीति (डीफ्लेशन) की प्रवृत्ति एक ऐसा जोखिम बनकर उभरी है, जिसके प्रभाव से आगामी कई वर्षों के लिए वैश्विक विकास के अवरुद्ध हो जाने का खतरा मंडरा रहा है. वैसे, यह एक दूसरी बात है कि कच्चे तेल तथा अधिकांश जिंसों की कीमतों में गिरावट से हमारी अर्थव्यवस्था को एक फौरी फायदा जरूर मिल गया है, क्योंकि इस वजह से हमें उस पर पड़े सब्सिडी-बोझ में कमी लाने का मौका मिल गया है. पर चूंकि इस वृहद आर्थिक परिदृश्य में कई और भी तत्व शामिल हैं, जिनके मद्देनजर देश के इस आगामी बजट के लिए कुछ अनुशंसाएं इस प्रकार की जा सकती हैं:

बजट को खासकर नियोजित पूंजीगत व्यय के हालिया दौर को कायम रखनेवाला होना चाहिए. दरअसल, पूंजीगत व्यय को इस वजह से सर्वोत्तम कोटि का व्यय माना जाता रहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसके बहुमुखी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जो दीर्घावधि आधार पर ही नजर आते हैं. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूंजीगत व्यय का प्रत्येक रुपया अर्थव्यवस्था के आउटपुट में अपने मूल्य की अपेक्षा 2.45 गुना अधिक विस्तार लाता है. इसलिए सड़कें और रेलवे समेत इससे संबद्ध अन्य क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए अधिक बड़े आवंटन की रणनीति अपनाना जरूरी होगा. इसके अंतर्गत, सार्वजनिक निधियों पर इस भांति बल दिया जाना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके. इस वृहद कोटि के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कम-से-कम एक लाख 20 हजार करोड़ रुपयों का आवंटन किये जाने की जरूरत होगी.

देश के आर्थिक विमर्श में धीरे-धीरे यह राय भी बलवती होती जा रही है कि इस बजट के मुतल्लिक सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से बहुत अधिक बंधा नहीं रहकर इस मोर्चे पर उसे लचीली रणनीति के संकेत देने चाहिए. मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि बजट 'राजकोषीय फिजूलखर्ची' की राह पर चला जाये, बल्कि यह है कि उसके द्वारा यह संकेत अवश्य दिया जाना चाहिए कि हमारी सरकार सार्वजनिक व्यय करने से पीछे नहीं हटेगी, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार से गतिशील रखा जा सके. इसी दलील के सहारे आगे चला जाये, तो यह कहा ही जाना चाहिए कि आम आदमी के लिए मुद्रास्फीति बहुत अधिक कष्टकारक होती है, क्योंकि वह अत्यंत निर्धनों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है. जैसा अर्थशास्त्री कहा करते हैं, मुद्रास्फीति 'गरीबों पर लादा गया कर' है. इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था की अब तक की प्रवृत्ति के मद्देनजर आगामी बजट के अंतर्गत ऐसे कदम अवश्य उठाये जाने चाहिए, जो जनता को मुद्रास्फीति के दबाव से राहत दे सकें.

इससे जुड़ा एक दूसरा मुद्दा मितव्ययिता का है, अन्य बातों के अलावा जिसका मतलब करों में वृद्धि तथा व्ययों में कमी लाना होता है. मेरी यह सलाह भी होगी कि हम अभी इस अवधारणा से हर हाल में दूरी बनाकर ही रखें, क्योंकि अभी की स्थिति में इसे अंगीकार करना गलत होगा. मैं कहना चाहूंगा कि आगामी बजट को 'भारत' के लिए होना चाहिए, जिसमें ग्रामीण जरूरतों पर खास ध्यान दिया जाये. दूसरे शब्दों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें आवश्यक कदमों की एक पूरी शृंखला का ही सहारा लेना होगा, जो उसके स्वरूप में सांगोपांग शक्ति का संचार कर उसे स्वस्थ बना सके.

केंद्रीय सरकार को बांधों (डैम), रोधक बांधों (चेक डैम), तालाबों इत्यादि के साथ ही सभी जल स्रोतों से संबद्ध सभी वैसी वर्तमान सिंचाई योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिनके लिए वह राज्य स्तर पर आर्थिक सहायता दिया करती है. इस क्षेत्र में एक नयी ऐसी योजना लायी जानी चाहिए, जिससे अंतरराज्यीय विवादों पर लगाम लग सके और देश के संसाधनों के समुचित उपयोग से सिंचित तथा कृषि योग्य भूमि के रकबे में बढ़ोतरी संभव हो सके. ऐसी योजना के विषय में यह आशा की जा सकती है कि वह सूखे के खतरे को कम करके खाद्य उपलब्धता पर भी सकारात्मक असर डालेगी.

स्वास्थ्य की देखरेख हेतु बीमा व्यवस्था के सार्वभौमीकरण की दिशा में प्रगति लाने हेतु भी जरूरी परिवर्तन लाये जाने चाहिए तथा गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे की वर्तमान विभेदकारी दृष्टि से भी अपने रास्ते अलग किये जाने चाहिए. इसकी बजाय, खाना पकाने की गैस पर दी जानेवाली सब्सिडी की ही तर्ज पर इसे आय-स्तर से जुड़ी किसी योजना से संबद्ध किया जाना चाहिए. इस नयी व्यवस्था के तहत, सरकार द्वारा जनता के सभी आय वर्गों हेतु स्वास्थ्य एवं दुर्घटना/दिव्यांगता बीमा को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए और केवल उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जानी चाहिए, जिन्हें सरकारी सहायता की जरूरत हो. ऐसी परिवर्तित योजना लोगों पर आ पड़नेवाले आकस्मिक मेडिकल व्ययों के कमरतोड़ बोझ में कमी लाते हुए एक सांस्कृतिक परिवर्तन की भी वाहक बनेगी, जहां स्वास्थ्य बीमा को केवल 'कर योजना निर्माण' के औजार के रूप में ही नहीं देखा जायेगा.

## आपके पत्र

### प्रेरक है यह कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश-विदेश से उन्हें उपहार में मिली वस्तुओं का देशहित में नीलामी का निर्णय वाकई सराहनीय है. ऐसे 1900 उपहारों की नीलामी के जरिये एकत्र होने वाली धनराशि को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दिये जाने की बात कही जा रही है. उल्लेखनीय है कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय मिले उपहारों को भी इसी प्रकार नीलाम किया जाता था, जिससे मिले पैसों को गरीब बच्चियों की पढ़ाई पर खर्च किया जाता था. इन कार्यों का महत्व भले सांकेतिक भर हो, फिर भी शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रस्तुत ऐसे उदाहरणों से जनसामान्य को प्रेरणा मिलती है कि वह भी अपने स्तर से राष्ट्र निर्माण के कार्य में, चाहे लघु स्तर पर ही सही, लेकिन भागीदारी अवश्य कर सकती है.

**चंदन कुमार,** देवघर.

### साइबर खतरों से बचाव जरूरी

साइबर खतरों के खिलाफ बने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन से जुड़े नेताओं ने भारत और अमेरिका से गठबंधन के साथ आने की अपील की है. स्विट्जरलैंड में आयोजित इस गठबंधन की सालाना बैठक में नेताओं और विशेषज्ञों ने इस बात का समर्थन भी किया है कि दुनिया को साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है. स्विट्जरलैंड के सम्मेलन में दिया गया यह न्योता भारत के लिए एक बड़ा मौका है. यह इस बात का संकेत है कि दुनिया जानती है कि फ्यूचर की लड़ाई बिना भारत के लड़ना आसान नहीं है. साइबर स्पेस में भरोसा और सुरक्षा के लिए काम करने के संबंध में 12 नवंबर 2018 को पेरिस काल नामक समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं, दुनिया अच्छी तरह जान चुकी है कि आइटी फील्ड में इंडियन प्रोफेशनल्स का कोई मुकाबला नहीं है. साइबर सिक्योरिटी की लड़ाई में यदि भारत शामिल होता है, तो यह उसके निजी हित में भी हैं. वजह यह है कि अपना देश साइबर सिक्योरिटी की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है. यदि भारत साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में महारत हासिल कर ले, तो दुनिया के अन्य देशों के लिए वह लीडर की भूमिका में होगा तथा ऐसा होना भारत के लिए अत्यंत गौरव की बात होगी.

**अमन सिंह,** प्रेमनगर, बरेली, यूपी

### भारत रत्न पर राजनीति

जब से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से इस पर राजनीति होती आयी है. सत्तारूढ़ दल अपने फायदे को देखते हुए नामों की घोषणा में प्रभावी भूमिका में होते हैं. 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी पर भी यह आरोप लगा था, जब उन्होंने एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न देने की घोषणा की थी, क्योंकि उसे ठीक बाद 1989 में तमिलनाडु में चुनाव हुआ था. वर्तमान सरकार के आने के बाद 2015 में मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था. इस साल तीन लोगों के नामों की घोषणा हुई है. भूपेन हजारिका, डॉ प्रणव मुखर्जी एवं नानाजी देशमुख. ऐसा लगता है कि ये नाम मतदाताओं को साधने के दृष्टि से चुने गये हैं.

**जंग बहादुर सिंह,** गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

## बोधि वृक्ष

# जीवन-समय

समय चलता रहता है. चीजें बदल जाती हैं. जब हम जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं, तो भावनात्मक चोट कहां रह जाती है, यह सोचते हैं. किसी ने कुछ कह दिया और हमें दुख पहुंचता है, और हम रोते हैं. किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, तो हम खुश हो जाते हैं. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कभी तुमने कुछ कह दिया और किसी को दुख हुआ, परंतु आपका यह इरादा नहीं था. क्या ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ? आपने अपनी बेटी या बेटे पर कितनी बार गुस्सा किया होगा, क्या आपने ऐसा नहीं किया? यदि वे जीवनभर इसे पकड़ के बैठ जायें और कहें कि मैं इसे नहीं भूलूंगा, आपने मुझे दुख पहुंचाया है, तो आप उनसे क्या कहोगे? आपका जवाब कुछ ऐसा होगा- 'जाने दो, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था. मैं तनाव में था, परेशान था, मेरा मूड खराब था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया.' क्या आप लोगों से अपेक्षा नहीं करते कि वे आपके द्वारा दिये गये दुख को भुला दें? आप चाहते हो आपके द्वारा दिया गया दुख लोग भुला दें. इसी तरह क्या आपको भी उनके द्वारा दिये गये दुख को भुला नहीं देना चाहिए? यदि आपने पढ़ना-लिखना नहीं सीखा है, तो क्या यह आपकी गलती है? आपके अध्यापक और माता-पिता आपको स्कूल ले जातें हैं, तब आप सीखते हो. उनके पास कोई तरीका नहीं था, जहां वे जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देख सकते. उन्हें सीखने का अवसर नहीं मिला, कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, इसलिए उन्हें आध्यात्मिकता का पता नहीं चला. तो आप किस बात को पकड़े रहोगे? जीवन आगे बढ़ रहा है. आपके अंत में आपसे दो बातें पूछी जायेंगी- आपने कितना प्रेम किया और आपने कितना ज्ञान जीवन में प्राप्त किया? इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोगों ने आपके साथ क्या किया, परंतु आपकी तरफ से करुणा होनी चाहिए. यदि लोग आपके प्रति अच्छे हैं, तो खुश रहो. यदि वे कुछ गलत करते हैं, तो दयावान रहो. जीवन केवल खुशी और करुणा के बीच चलता है.

**श्रीश्री रविशंकर**

## कुछ अलग

# किताबों के मेले में महिलाएं

**क्षमा शर्मा**
वरिष्ठ पत्रकार
kshamasharma1@gmail.com

**हाल** ही में दिल्ली विश्व पुस्तक मेला खत्म हुआ. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित पुस्तकों के इस महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं. सैकड़ों लेखकों की पुस्तकों का लोकार्पण होता है. लेखक और प्रकाशक यही चाहते हैं कि पुस्तकें मेले के अवसर पर आयें और इसी बहाने मीडिया में कवरेज और चर्चा भी हो जाये.

जैसे-जैसे पुस्तकें लोकार्पित हुईं, वे फेसबुक और सोशल मीडिया में अपनी जगह बनाती गयीं. किसने क्या बोला, यह भी पता चलता गया. इस बार दिलचस्प बात यह थी कि महिलाओं की किताबें बहुत बड़ी संख्या में लोकार्पित हुईं. इनमें कहानी, कविताएं, उपन्यास, आलोचना, राजनीति के अलावा विविध विषयों की किताबें थीं. इन्हें देखकर यह बात साबित हुई कि देशभर में अब बड़ी संख्या में औरतें लिख रही हैं. ये युवा हैं, मिडिल एज्ड हैं, सीनियर सिटिजन हैं, यानी कि लेखन में महिला की उम्र कोई बाधा नहीं है. इसीलिए शायद बहुत से लोग कहने लगे हैं कि यह साहित्य का महिला युग है. वे पुरुषों से भी बड़ी संख्या में लेखन के क्षेत्र में दस्तक दे रही हैं.

मेले में सिर्फ लेखिकाओं के रूप में ही नहीं, दर्शक और खरीदार के रूप में भी महिलाएं खूब दिखीं. बहुत सी युवा माताएं अपने बच्चों की उंगली पकड़े आती थीं. बच्चे किताबों को छूकर देखते थे. उनके चित्रों को पलटते थे. फिर माताएं उनकी उम्र और रुचि के हिसाब से किताबें खरीदती थीं. बच्चों के लिए उनकी रुचियों और जरूरतों को देखते हुए मेले में हर बार ढेरों किताबें होती हैं. इस बार भी थीं.

स्कूल, कॉलेज में पढ़ती बच्चियां, नौकरी-पेशा लड़कियां भी इस स्टॉल से उस स्टॉल पर आती-जाती दिखीं. वे सबसे अधिक जोश में थीं. बहुत-सारी लड़कियां तो स्टॉल्स के बाहर धूप में बैठकर, कुछ-न-कुछ खाती और किताब पढ़ती नजर आयीं.

आज से दो-चार पीढ़ी पहले स्त्री के जीवन में किताब की भूमिका मात्र इतनी ही थी कि वह पढ़ना-लिखना सीख जाये, जिससे कि समय-समय पर अपनी राजी-खुशी की जानकारी वह चिट्ठी के जरिये अपने घर वालों को दे सके. या फिर रामायण, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ सके, जिससे कि उसकी पूजा में कोई विघ्न न पड़े. कुछ और समय बीता, तो कहा जाने लगा कि लड़कियां पुस्तकों को पढ़ें, ताकि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें. बाकायदा विज्ञापनों में गणित और साइंस पढ़ी-लिखी लड़की की मांग की जाती थी, ताकि बच्चों के लिए इन विषयों का ट्यूशन न लगाना पड़े.

लेकिन, लेखन के क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं की उपस्थिति यह बताती है कि अब वे अपनी जिंदगी को देखने और रचने के लिए किसी और की कलम की मोहताज नहीं हैं. वे न केवल अपने बारे में, बल्कि दुनिया के बारे में अपने नजरिये को घर-घर तक पहुंचा सकती हैं. प्रशंसित हो सकती हैं और तमाम पुरानी वर्जनाओं को तोड़ सकती हैं. और दूसरों को उन्हें तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं.

## देश दुनिया से

# कोयले का इस्तेमाल बंद करना चाहता है जर्मनी

**जर्मनी** कोयले का इस्तेमाल खत्म करना चाहता है. मगर ऐसा करने के लिए कारोबार, रोजगार और बाकी की बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा. इसलिए जर्मन सरकार ने 28 विशेषज्ञों का पैनल बनाया है, जो इस समस्या का हल निकाल सके. हालांकि, अभी तक इस पैनल को कोई उपाय नहीं मिला है. साल 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में जर्मनी ने वादा किया था कि वह अपना ग्लोबल वॉर्मिंग का लक्ष्य दो डिग्री सेल्सियस के नीचे रखेगा. इसके लिए ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत तेजी से कम करने की जरूरत होगी. जर्मनी के कोयले के कारखाने पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं. माना जा रहा है कि जर्मनी पेरिस जलवायु समझौते में 2020 के लिए दिया हुआ लक्ष्य पूरा नहीं कर पायेगा. देश में काले कोयले की खदानों को तो बंद कर दिया गया है, मगर विदेशों से जीवाश्म ईंधन अब भी आयात होता है. जर्मनी में अभी भी लिग्नाइट निकाला और जलाया जाता है, जो की एक सस्ता और गंदे प्रकार का कोयला है. इससे देश कि एक तिहाई बिजली पैदा होती है. कोयले का इस्तेमाल बंद करने से जर्मनी अपना साल 2030 और 2050 का लक्ष्य हासिल कर सकेगा, जिसके लिए 55 और 80 प्रतिशत कोयले का इस्तेमाल कम करना होगा.

## कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

**पोस्ट करें** : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
**मेल करें** : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है